



All Inclusive IAS – CSAT through PYQs

← Explanation video in English

Class-06

हिंदी में स्पष्टीकरण वीडियो →



2014 Set-A

Directions for the following 5 (five) items: Read the following two passages and answer the items that follow each passage. Your answers to these items should be based on the passages only.

Passage (Set-A Q. 1-3)

In recent times, India has grown fast not only compared to its own past but also in comparison with other nations. But there cannot be any room for complacency because it is possible for the Indian economy to develop even faster and also to spread the benefits of this growth more widely than has been done thus far. Before going into details of the kinds of micro-structural changes that we need to conceptualize and then proceed to implement, it is worthwhile elaborating on the idea of inclusive growth that constitutes the defining concept behind this Government's various economic policies and decisions. A nation interested in inclusive growth views the same growth differently depending on whether the gains of the growth are heaped primarily on a small segment or shared widely by the population. The latter is cause for celebration but not the former. In other words, growth must not be treated as an end in itself but as an instrument for spreading prosperity to all. India's own past experience and the experience of other nations suggests that growth is necessary for eradicating poverty but it is not a sufficient condition. In other words, policies for promoting growth need to be complemented with policies to ensure that more and more people join in the growth process and, further, that there are mechanisms in place to redistribute some of the gains to those who are unable to partake in the market process and, hence, get left behind.

A simple way of giving this idea of inclusive growth a sharper form is to measure a nation's progress in terms of the progress of its poorest segment, for instance the bottom 20 per cent of the population. One could measure the per capita income of the bottom quintile of the population and also calculate the growth rate of income; and evaluate our economic success in terms of these measures that pertain to the poorest segment. This approach is attractive because it does not ignore growth like some of the older heterodox criteria did. It simply looks at the growth of income of the poorest sections of the population. It also ensures that those who are outside of the bottom quintile do not get ignored. If that were done, then those people would in all likelihood drop down into the bottom quintile and so would automatically become a direct target of our policies. Hence the criterion being suggested here is a statistical summing up of the idea of inclusive growth, which, in turn, leads to two corollaries: to wish that India must strive to achieve high growth and that we must work to ensure that the weakest segments benefit from the growth.

निम्नलिखित 5 (पाँच) प्रश्नों के लिए निर्देश: निम्नलिखित दो परिच्छेदों को पढ़िए और प्रत्येक परिच्छेद के आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों के आपके उत्तर इन परिच्छेदों पर ही आधारित होने चाहिए।

परिच्छेद (Set-A Q. 1-3)

हाल के वर्षों में, भारत न केवल खुद अपने अतीत की तुलना में, बल्कि अन्य देशों की तुलना में भी, तेज़ी से विकसित हुआ है। किन्तु इसमें किसी आत्मसंतोष की गुंजाइश नहीं हो सकती, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इससे भी अधिक तीव्र विकास करना और इस संवृद्धि के लाभों को, अब तक जितना किया गया है उससे कहीं अधिक व्यापक रूप से, अधिकाधिक लोगों तक पहुँचाना सम्भव है। उन सूक्ष्म-संरचनात्मक परिवर्तनों के प्रकारों के ब्यौरों में जाने से पहले, जिनकी हमें संकल्पना करने और फिर उन्हें कार्यान्वित करने की ज़रूरत है, समावेशी संवृद्धि के विचार को विस्तार से देखना सार्थक होगा, जो कि इस सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों और निर्णयों के पीछे एक निरूपक संकल्पना निर्मित करता है। समावेशी संवृद्धि में रुचि रखने वाला राष्ट्र इसी संवृद्धि को एक भिन्न रूप में देखता है जो इस पर आधारित है कि क्या संवृद्धि के लाभों का जनसंख्या के एक छोटे हिस्से पर ही अम्बार लगा दिया गया है या इनमें सभी लोगों की व्यापक रूप से साझेदारी है। अगर संवृद्धि के लाभों में व्यापक रूप से साझेदारी है तो यह खुशी की बात है, पर अगर संवृद्धि के लाभ एक हिस्से पर ही केंद्रित हैं, तो नहीं। दूसरे शब्दों में, संवृद्धि को अपने आप में एक साध्य की तरह नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे सभी तक संपन्नता पहुँचाने के एक साधन के रूप में देखा जाना चाहिए। भारत के स्वयं के अतीत के अनुभव तथा दूसरे राष्ट्रों के अनुभव भी, यह सुझाते हैं कि संवृद्धि गरीबी के उन्मूलन के लिए आवश्यक तो है परन्तु यह एक पर्याप्त शर्त नहीं है। दूसरे शब्दों में, संवृद्धि को बढ़ाने की नीतियों को ऐसी और नीतियों से सम्पूरित किया जाना आवश्यक है जो यह सुनिश्चित करें कि अधिकाधिक लोग संवृद्धि की प्रक्रिया में शामिल हों, और यह भी, कि ऐसी क्रियाविधियाँ उपलब्ध हों जिनसे कुछ लाभ ऐसे लोगों में पुनर्वितरित किए जाएँ जो बाज़ार-प्रक्रिया में भागीदार होने में अक्षम हैं और इस कारण पीछे छूट जाते हैं।

समावेशी संवृद्धि के इस विचार को एक अधिक सुस्पष्ट रूप देने का एक सरल तरीका यह है कि किसी राष्ट्र की उन्नति को उसके सबसे गरीब हिस्से, उदाहरणार्थ, जनसंख्या के सबसे निचले 20%, की उन्नति के आधार पर मापा जाए। जनसंख्या के इस सबसे निचले पाँचवें हिस्से की प्रति व्यक्ति आय को मापा जा सकता है और आय की वृद्धि-दर की गणना भी की जा सकती है; और सबसे गरीब हिस्से से सम्बन्धित इन मापकों के आधार पर हमारी आर्थिक सफलता का आकलन किया जा सकता है। यह दृष्टि आकर्षक है, क्योंकि यह संवृद्धि की उस तरह उपेक्षा नहीं करती जैसी कि कुछ पहले के परम्पराविरुद्ध मानदण्डों में की जाती थी। यह बस जनसंख्या के सबसे गरीब हिस्से की आय की वृद्धि को ही देखती है। यह इसे भी सुनिश्चित करती है कि ऐसे लोगों की भी उपेक्षा न हो जो इस निचले पाँचवें हिस्से से बाहर हैं। अगर ऐसा हो, तो पूरी सम्भावना है कि वे लोग भी इस निचले पाँचवें हिस्से में आ जाएँ और इस प्रकार अपने-आप ही हमारी इन नीतियों का सीधा लक्ष्य बन जाएँ। इस प्रकार यहाँ सुझाए गए मानदण्ड समावेशी संवृद्धि के विचार का सांख्यिकीय समाकलन हैं जो परिणामतः दो उपसिद्धांतों की ओर ले जाते हैं: यह इच्छा करना कि आवश्यक रूप से भारत ऊँची संवृद्धि प्राप्त करने का प्रयास करे और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए कार्य करें कि संवृद्धि से सबसे गरीब हिस्से लाभान्वित हो।

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

www.allinclusiveias.com

UPSC / PCS CSAT

Class-06

Page-040

© All Inclusive IAS

<p>1 The author's central focus is on</p> <p>(a) applauding India's economic growth not only against its own past performance, but against other nations.</p> <p>(b) emphasizing the need for economic growth which is the sole determinant of a country's prosperity.</p> <p>(c) emphasizing inclusive growth where gains of growth are shared widely by the population.</p> <p>(d) emphasizing high growth.</p> <p>2 The author supports policies which will help</p> <p>(a) develop economic growth.</p> <p>(b) better distribution of incomes irrespective of rate of growth.</p> <p>(c) develop economic growth and redistribute economic gains to those getting left behind.</p> <p>(d) put an emphasis on the development of the poorest segments of society.</p> <p>3 Consider the following statements: According to the author, India's economy has grown but there is no room for complacency as</p> <p>1. growth eradicating poverty.</p> <p>2. growth has resulted in prosperity for all.</p> <p>Which of the statements given above is/are correct?</p> <p>(a) 1 only (b) 2 only (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2</p> <p><i>Reasons given in lines 4-5-6</i></p> <p>1. <i>It is possible for economy to develop even faster</i></p> <p>2. <i>It is possible to spread benefits more widely</i></p> <p><i>Hence, both statements given in question are wrong.</i></p> <p>Official Answer key: 1 - c 2 - c 3 - d</p>	<p>1 इस परिच्छेद में, लेखक की दृष्टि का केन्द्र बिन्दु क्या है?</p> <p>(a) भारत की, न केवल इसके खुद के पूर्व के निष्पादन की तुलना में बल्कि अन्य राष्ट्रों की तुलना में भी, आर्थिक संवृद्धि की प्रशंसा करना</p> <p>(b) आर्थिक संवृद्धि की आवश्यकता पर बल देना, जो देश की संपन्नता की एकमात्र निर्धारक है</p> <p>(c) उस समावेशी संवृद्धि पर बल देना, जिसमें जनसंख्या व्यापक रूप से संवृद्धि के लाभों में सहभागी होती है</p> <p>(d) उच्च संवृद्धि पर बल देना</p> <p>2 इस परिच्छेद में, लेखक उन नीतियों का समर्थन करता है, जो</p> <p>(a) आर्थिक संवृद्धि को बढ़ाने में सहायक होंगी</p> <p>(b) आय के बेहतर वितरण में सहायक होंगी, चाहे वृद्धि दर कुछ भी हो</p> <p>(c) आर्थिक संवृद्धि बढ़ाने और आर्थिक उपलब्धियों को उनमें पुनर्वितरित करने में सहायक होंगी, जो पीछे छूट रहे हैं</p> <p>(d) समाज के सबसे गरीब हिस्सों के विकास पर बल देने में सहायक होंगी</p> <p>3 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : लेखक के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है किन्तु यहाँ आत्मसंतोष के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि</p> <p>1. संवृद्धि से गरीबी का उन्मूलन होता है</p> <p>2. वृद्धि सभी की सम्पन्नता में परिणमित हुई है</p> <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2</p> <p><i>पंक्तियों 4-5-6 में दिए गए कारण :</i></p> <p>1. <i>अर्थव्यवस्था का और भी तेजी से विकास संभव है</i></p> <p>2. <i>लाभों को अधिक व्यापक रूप से फैलाना संभव है</i></p> <p><i>अतः प्रश्न में दिए गए दोनों कथन गलत हैं।</i></p>
---	--

<p>Passage (Set-A Q. 4-5)</p> <p>It is easy for the government to control State-owned companies through nods and winks. So what really needs to be done as a first step is to put petrol pricing on a transparent formula — if the price of crude is x and the exchange rate y, then every month or fortnight, the government announces a maximum price of petrol, which anybody can work out from the x and the y. The rule has to be worked out to make sure that the oil-marketing companies can, in general, cover their costs. This will mean that if one company can innovate and cut costs, it will make greater profits. Hence, firms will be more prone to innovate and be efficient under this system. Once the rule is announced, there should be no interference by the government. If this is done for a while, private companies will re-enter this market. And once a sufficient number of them are in the fray, we can remove the rule-based pricing and leave it truly to the market (subject to, of course, the usual regulations of antitrust and other competition laws).</p> <p>4 Consider the following statements: According to the passage, an oil company can make greater profits, if a transparent formula for petrol pricing is announced every fortnight or month, by</p> <p>1. promoting its sales.</p> <p>2. undertaking innovation.</p> <p>3. cutting costs.</p> <p>4. selling its equity shares at higher prices.</p> <p>Which of the statements given above is/are correct?</p> <p>(a) 1 only (b) 2 and 3 (c) 3 and 4 (d) 1, 2 and 4</p>	<p>परिच्छेद (Set-A Q. 4-5)</p> <p>सरकार के लिए राज्य के स्वामित्व वाली कम्पनियों को प्रायः सहमति और अनदेखी से नियंत्रित करना आसान है। इसलिए पहले कदम के रूप में वास्तव में यह करने की जरूरत है कि पेट्रोल के कीमत-निर्धारण को एक पारदर्शी सूत्र पर आधारित किया जाए - यदि कच्चे तेल की कीमत x और विनिमय दर y हो, तब हर महीने अथवा पखवाड़े पर, सरकार पेट्रोल की अधिकतम कीमत की घोषणा करे, तो उसे कोई भी व्यक्ति x और y के आधार पर परिकलित कर सकता है। यह सुनिश्चित करने हेतु नियम बनाया जाना चाहिए कि तेल का विपणन करने वाली कम्पनियाँ सामान्य रूप से, अपनी लागतें प्राप्त कर सकें। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई कम्पनी नवप्रवर्तनों से अपनी लागतों को कम कर ले, तो वह और अधिक लाभ प्राप्त करेगी। इस प्रकार, इस प्रणाली के अंतर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठान नवप्रवर्तनों की ओर अधिक प्रवृत्त और दक्ष हो जाएँगे। एक बार नियम की घोषणा हो जाए, तो सरकार की तरफ से फिर कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। यदि कुछ समय के लिए ऐसा कर दिया जाए, तो प्राइवेट कम्पनियाँ इस बाजार में पुनः प्रवेश करेंगी। और जब एक बार उनकी पर्याप्त संख्या बाजार में आ जाए, तो हम नियम-आधारित कीमत-निर्धारण को हटा सकते हैं और इसे वास्तविक रूप में बाजार पर छोड़ा जा सकता है (निश्चित रूप से सामान्य एंटी-ट्रस्ट (न्यास-विरोधी) विनियमों व अन्य प्रतिस्पर्धी कानूनों के अधीन रहते हुए)।</p> <p>4 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : परिच्छेद के अनुसार, कोई तेल कम्पनी और अधिक लाभ कमा सकती है, यदि पेट्रोल के कीमत-निर्धारण हेतु एक पारदर्शी सूत्र प्रति पखवाड़े या माह घोषित किया जाए,</p> <p>1. इसके विक्रय को बढ़ाकर</p> <p>2. नवप्रवर्तनों के द्वारा</p> <p>3. लागतों में कमी करके</p> <p>4. इसके इक्विटी शेयरों को ऊँची कीमतों पर बेच कर</p> <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 1 (b) 2 और 3 (c) 3 और 4 (d) 1, 2 और 4</p>
---	---

<p>5 Consider the following statements: According to the passage, private oil companies re-enter the oil producing market if</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. a transparent rule-based petrol pricing exists. 2. there is no government interference in the oil producing market. 3. subsidies are given by the government. 4. regulations of anti-trust are removed. <p>Which of the statements given above are correct? (a) 1 and 2 (b) 2 and 3 (c) 3 and 4 (d) 2 and 4</p> <p>Official Answer key: 4 - b 5 - a</p>	<p>5 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : परिच्छेद के अनुसार, प्राइवेट तेल कम्पनियाँ तेल उत्पादन के बाज़ार में पुनः प्रवेश करती हैं, यदि—</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. एक पारदर्शी नियम-आधारित पेट्रोल का कीमत-निर्धारण अस्तित्व में हो 2. तेल उत्पादन के बाज़ार में सरकार का कोई हस्तक्षेप न हो 3. सरकार द्वारा उपदान दिए जाते हों 4. एंटी-ट्रस्ट (न्यास-विरोधी) के विनियमों को हटा दिया गया हो <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) 1 और 2 (b) 2 और 3 (c) 3 और 4 (d) 2 और 4</p>
<p style="text-align: center;">Passage (Set-A Q. 13,14)</p> <p>Climate change poses potentially devastating effects on India's agriculture. While the overall parameters of climate change are increasingly accepted — a 1°C average temperature increase over the next 30 years, sea level rise of less than 10 cm in the same period, and regional monsoon variations and corresponding droughts — the impacts in India are likely to be quite site and crop specific. Some crops may respond favourably to the changing conditions, others may not. This emphasizes the need to promote agricultural research and create maximum flexibility in the system to permit adaptations.</p> <p>The key ingredient for “drought proofing” is the managed recharge of aquifers. To ensure continued yields of important staple crops (e.g. wheat), it may also be necessary to shift the locations where these crops are grown, in response to temperature changes as well as to water availability. The latter will be a key factor in making long term investment decisions. For example, water runoff from the Himalayas is predicted to increase over the next 30 years as glaciers melt, but then decline substantially thereafter. It will be critical to provide incentives to plan for these large-scale shifts in agro-ecological conditions. India needs to make long term investment in research and development in agriculture. India is likely to experience changed weather patterns in future.</p> <p>13 Consider the following statements: Climate change may force the shifting of locations of the existing crops due to</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melting of glaciers. 2. water availability and temperature suitability at other locations. 3. poor productivity of crops. 4. wider adaptability of crop plants. <p>Which of the statements given above are correct? (a) 1, 2 and 3 (b) 2 and 3 only (c) 1 and 4 only (d) 1, 2, 3 and 4</p> <p>14 According to the passage, why is it important to promote agricultural research in India?</p> <ol style="list-style-type: none"> a) To predict variations in monsoon patterns and to manage water resources b) To make long term investment decisions for economic growth c) To facilitate wider adaptability of crops d) To predict drought conditions and to recharge aquifers <p>Official Answer key: 13 - b 14 - c</p>	<p style="text-align: center;">परिच्छेद (Set-A Q. 13-14)</p> <p>जलवायु परिवर्तन, भारत की कृषि पर संभावित रूप से विध्वंसकारी प्रभाव रखता है। जबकि, जलवायु परिवर्तन के समग्र प्राचल वर्धमानतः स्वीकृत हैं— अगले 30 वर्ष में 1°C की औसत ताप वृद्धि, इसी अवधि में 10 cm से कम की समुद्र तल वृद्धि और क्षेत्रीय मानसून विचरण तथा संगत अनावृष्टि — भारत में प्रभाव काफी स्थल एवं फसल विशिष्ट होने संभावित हैं। कुछ फसलें परिवर्तनशील दशाओं के प्रति अनुकूल प्रतिक्रिया दे सकती हैं, दूसरी नहीं भी दे सकती हैं। इससे कृषि अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और प्रणाली में अनुकूलन हो सके इस हेतु, अधिकतम नम्यता बनाने की आवश्यकता पर बल पड़ता है।</p> <p>“अनावृष्टि रोधन” का मुख्य संघटक अंतःजलस्तर का प्रबंधित पुनर्भरण है। महत्वपूर्ण आधारीक फसलों (जैसे, गेहूँ) की लगातार उपज सुनिश्चित करने के लिए, ताप परिवर्तनों तथा जल उपलब्धता को देखते हुए इन फसलों की उगाई वाले स्थानों को बदलना भी आवश्यक हो सकता है। दीर्घावधि निवेश के निर्णय करने में जल उपलब्धता एक मुख्य कारक होगा। उदाहरण के लिए, अगले 30 वर्षों में जैसे-जैसे हिमनद पिघलते जाते हैं, हिमालय क्षेत्र से जल के बहाव के बढ़ते जाने और तदनंतर अत्यधिक घटते जाने का पूर्वानुमान किया गया है। कृषि-पारिस्थितिक दशाओं में बड़े पैमाने पर आने वाले इन बदलावों के लिए योजना बनाने हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना निर्णायक होगा। भारत के लिए कृषि अनुसंधान और विकास में दीर्घावधि निवेश करना आवश्यक है। यह संभावित है कि भारत को भविष्य में एक बदले हुए मौसम प्रतिरूप का सामना करना होगा।</p> <p>13 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए : जलवायु परिवर्तन वर्तमान फसलों के स्थानों में बदलाव लाने के लिए किस कारण से मजबूर करेंगे?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. हिमनदों का पिघलना 2. दूसरे स्थानों पर जल उपलब्धता और ताप उपयुक्तता 3. फसलों की हीन उत्पादकता। 4. सस्य पादपों की अपेक्षाकृत व्यापक अनुकूलता <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन-से सही हैं? (a) 1, 2 और 3 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 4 (d) 1, 2, 3 और 4</p> <p>14 इस परिच्छेद के अनुसार, भारत में कृषि अनुसंधान को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण क्यों है?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) मानसून प्रतिरूपों में विचरण का पूर्वानुमान करना और जल संसाधनों का प्रबंधन करना (b) आर्थिक संवृद्धि के लिए दीर्घावधि निवेश के निर्णय करना (c) फसलों की व्यापक अनुकूलता को सुकर बनाना (d) अनावृष्टि दशाओं का पूर्वानुमान करना और अंतः जलस्तरों का पुनर्भरण करना

Separate explanation videos are available in English & Hindi अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

Passage (Set-A Q. 15-18)

It is essential that we mitigate the emissions of greenhouse gases and thus avoid some of the worst impacts of climate change that would take place in coming years and decades. Mitigation would require a major shift in the way we produce and consume energy. A shift away from overwhelming dependence on fossil fuels is now long overdue, but unfortunately, technological development has been slow and inadequate largely because government policies have not promoted investments in research and development, myopically as a result of relatively low prices of oil. It is now, therefore, imperative for a country like India treating the opportunity of harnessing renewable energy on a large scale as a national imperative. This country is extremely well endowed with solar, wind and biomass sources of energy. Where we have lagged, unfortunately, is in our ability to develop and to create technological solutions for harnessing these resources.

One particular trajectory for carrying out stringent mitigation of greenhouse gas emissions assessed by the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) clearly shows the need for ensuring that global emissions of greenhouse gases peak no later than 2015 and reduce rapidly thereafter. The cost associated with such a trajectory is truly modest and would amount, in the estimation of IPCC, to not more than 3 percent of the global GDP in 2030. In other words, the level of prosperity that the world would have reached without mitigation would at worst be postponed by a few months or a year at the most. This is clearly not a very high price to pay for protecting hundreds of millions of people from the worst risks associated with climate change. Any such effort, however, would require lifestyles to change appropriately also. Mitigation of greenhouse gas emissions is not a mere technological fix, and clearly requires changes in lifestyles and transformation of a country's economic structure, whereby effective reduction in emissions is brought about, such as through the consumption of much lower quantities of animal protein. The Food and Agriculture Organization (FAO) has determined that the emissions from the livestock sector amount to 18 percent of the total. The reduction of emissions from this source is entirely in the hands of human beings, who have never questioned the impacts that their dietary habits of consuming more and more animal protein are bringing about. Mitigation overall has huge co-benefits, such as lower air pollution and health benefits, higher energy security and greater employment.

15 According to the passage, which of the following would help in the mitigation of greenhouse gases?

1. Reducing the consumption of meat
2. Rapid economic liberalization
3. Reducing the consumerism
4. Modern management practices of livestock

Select the correct answer using the code given below:

- (a) 1, 2 and 3 (b) 2, 3 and 4
(c) 1 and 3 only (d) 2 and 4 only

परिच्छेद (Set-A Q. 15-18)

यह परमावश्यक है कि हम ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन घटाएँ और इस तरह आगामी वर्षों और दशकों में होने वाले जलवायु परिवर्तन के कुछ बदतर प्रभावों से बचें। उत्सर्जन कम करने के लिए ऊर्जा के उत्पादन और उपभोग के हमारे तरीकों में एक बड़ा बदलाव अपेक्षित होगा। जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भरता से हटना अतिविलम्बित है, किन्तु दुर्भाग्य से, प्रौद्योगिकीय विकास धीमा और अपर्याप्त रहा है, मोटे तौर पर इसलिए, कि तेल की अपेक्षाकृत निम्न कीमतों से जन्मी अदूरदर्शिता के कारण सरकारी नीतियाँ अनुसंधान और विकास में निवेश को प्रोत्साहन नहीं देती रही हैं। इसलिए अब राष्ट्रीय अनिवार्यता के रूप में वृहत् पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा को काम में लाने के अवसर का लाभ उठाना भारत जैसे देश के लिए अत्यावश्यक है। यह देश ऊर्जा के सौर, वायु और जैवमात्रा स्रोतों से अत्यधिक सम्पन्न है। दुर्भाग्य से, जहाँ हम पीछे हैं, वह है इन स्रोतों को काम में लाने के लिए प्रौद्योगिकीय समाधान विकसित और सर्जित करने की हमारी क्षमता।

जलवायु परिवर्तन पर अंतः सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा निर्धारित रूप में ग्रीनहाउस गैसों को सख्ती से कम करने के लिए एक विशिष्ट प्रक्षेप-पथ स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता को दिखाता है कि ग्रीनहाउस गैसों के भूमंडलीय उत्सर्जनों का चरम बिन्दु 2015 को पार न करे और उसके आगे तेजी से घटने लगे। ऐसे प्रक्षेप-पथ के साथ संबद्ध लागत वस्तुतः मर्यादित है और इसकी राशि, IPCC के आकलन में, 2030 में विश्व GDP के 3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, सम्पन्नता के जिस स्तर पर विश्व बिना उत्सर्जन में कमी लाए पहुँच सकता, खराब-से-खराब हालत में कुछ मास या अधिक-से-अधिक एक वर्ष तक टल जाएगी। स्पष्टतः यह, जलवायु परिवर्तन से जुड़े बदतर खतरों से करोड़ों लोगों को बचाने के लिए चुकाई जाने वाली कोई बहुत बड़ी कीमत नहीं है। तथापि, ऐसे किसी प्रयास के लिए जीवन-शैलियों को भी उपयुक्त रूप से बदलना होगा। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाना सिर्फ एक प्रौद्योगिकीय उपाय भर नहीं है, और इसके लिए स्पष्टतः जीवन-शैलियों में बदलाव और देश की आर्थिक संरचना में रूपांतरण अपेक्षित है, जिसके द्वारा, उत्सर्जन को प्रभावी रूप से कम किया जाए, जैसे कि जीव प्रोटीन के काफी कम मात्राओं में उपभोग के माध्यम से। खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने यह निर्धारित किया है कि पशुधन क्षेत्रक से उत्सर्जन कुल उत्सर्जन का 18 प्रतिशत होता है। इस स्रोत से हो रहे उत्सर्जन में कमी लाना पूरी तरह मनुष्यों के हाथ में है, जिन्होंने अपनी अधिक-से-अधिक जीव प्रोटीन के उपभोग की आहार-आदतों के कारण पड़ने वाले प्रभाव पर कभी कोई प्रश्न नहीं उठाया। वस्तुतः उत्सर्जन में कमी लाने के विशाल सह-सुलाभ हैं, जैसे अपेक्षाकृत कम वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य संबंधी लाभ, उच्चतर ऊर्जा सुनिश्चितता तथा और अधिक रोजगार।

15 परिच्छेद के अनुसार, निम्नलिखित में से कौन-से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने में सहायक होंगे?

1. माँस के उपभोग में कमी लाना
2. तीव्र आर्थिक उदारीकरण
3. उपभोक्तावाद में कमी लाना
4. पशुधन की आधुनिक प्रबंधन प्रक्रियाएँ

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:

- (a) 1, 2 और 3 (b) 2, 3 और 4
(c) केवल 1 और 3 (d) केवल 2 और 4

<p>16 Why do we continue to depend on the fossil fuels heavily?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inadequate technological development 2. Inadequate funds for research and development 3. Inadequate availability of alternative sources of energy <p>Select the correct answer using the code given below:</p> <p>(a) 1 only (b) 2 and 3 only (c) 1 and 3 only (d) 1, 2 and 3</p> <p>17 According to the passage, how does the mitigation of greenhouse gases help us?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Reduces expenditure on public health 2. Reduces dependence on livestock 3. Reduces energy requirements 4. Reduces rate of global climate change <p>Select the correct answer using the code given below:</p> <p>(a) 1, 2 and 3 (b) 1, 3 and 4 (c) 2, 3 and 4 (d) 1 and 4 only</p> <p>18 What is the essential message of the passage?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) We continue to depend on fossil fuels heavily (b) Mitigation of the greenhouse gases is imperative (c) We must invest in research and development (d) People must change their lifestyle <p>Official Answer key: 15 - c 16 - d 17 - b 18 - b</p>	<p>16 हम जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर क्यों बने हुए हैं?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय विकास 2. अनुसंधान और विकास के लिए अपर्याप्त निधियाँ 3. ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों की अपर्याप्त उपलब्धता <p>नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:</p> <p>(a) केवल 1 (b) केवल 2 और 3 (c) केवल 1 और 3 (d) 1, 2 और 3</p> <p>17 परिच्छेद के अनुसार, ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाना हमारे लिए किस तरह सहायक है?</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इससे लोक स्वास्थ्य पर व्यय घटता है 2. इससे पशुधन पर निर्भरता घटती है 3. इससे ऊर्जा आवश्यकताएँ घटती हैं 4. इससे भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन की दर घटती है <p>नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए:</p> <p>(a) 1, 2 और 3 (b) 1, 3 और 4 (c) 2, 3 और 4 (d) केवल 1 और 4</p> <p>18 इस परिच्छेद का सारभूत संदेश क्या है?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) हम जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर बने हुए हैं (b) ग्रीनहाउस गैसों में कमी लाना अत्यावश्यक है (c) हमें अनुसंधान और विकास में निवेश करना ही चाहिए (d) लोगों को अपनी जीवन-शैली बदलनी ही चाहिए
---	--

Passage (Set-A Q. 26-29)

The Himalayan ecosystem is highly vulnerable to damage, both due to geological reasons and on account of the stress caused by increased pressure of population, exploitation of natural resources and other related challenges. These aspects may be exacerbated due to the impact of climate change. It is possible that climate change may adversely impact the Himalayan ecosystem through increased temperature, altered precipitation patterns, episodes of drought and biotic influences. This would not only impact the very sustenance of the indigenous communities in uplands but also the life of downstream dwellers across the country and beyond. Therefore, there is an urgent need for giving special attention to sustain the Himalayan ecosystem. This would require conscious efforts for conserving all the representative systems.

Further, it needs to be emphasized that the endemics with restricted distribution, and most often with specialized habitat requirements, are among the most vulnerable elements. In this respect the Himalayan biodiversity hotspot, with rich endemic diversity, is vulnerable to climate change. The threats include possible loss of genetic resources and species, habitats and concomitantly a decrease in ecosystem services. Therefore, conservation of endemic elements in representative ecosystems/ habitats assumes a great significance while drawing conservation plans for the region.

Towards achieving the above, we will have to shift toward contemporary conservation approaches, which include a paradigm of landscape level interconnectivity between protected area systems. The concept advocates a shift from the species-habitat focus to an inclusive focus on expanding the biogeographic range so that natural adjustments to climate change can proceed without being restrictive.

परिच्छेद (Set-A Q. 26-29)

हिमालय का पारितंत्र भू-वैज्ञानिक कारणों और जनसंख्या के बढ़े हुए बोझ, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन और अन्य सम्बन्धित चुनौतियों से जन्म दबाव के कारण, क्षति के प्रति अत्यंत सुभेद्य है। सुभेद्यता के ये पहलू जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण उत्तेजित हो सकते हैं। यह सम्भव है कि जलवायु परिवर्तन हिमालय के पारितंत्र पर, बढ़े हुए तापमान, परिवर्तित वर्षण प्रतिरूप, अनावृष्टि की घटनाओं और जीवीय प्रभावों के माध्यम से, प्रतिकूल प्रभाव डाले। यह न केवल उच्चभूमियों में रहने वाले देशज समुदायों के पूरे निर्वाह पर, बल्कि सारे देश में और उसके परे अनुप्रवाह क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के जीवन पर भी असर डालेगा। इसलिए, हिमालय के पारितंत्र की धारणीयता बनाए रखने के लिए विशेष ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता है। इसके लिए सभी निरूपक प्रणालियों के संरक्षण के लिए सचेत प्रयत्न करने की आवश्यकता होगी।

आगे, इस पर बल देने की आवश्यकता है कि सीमित व्याप्ति वाले, और बहुधा विशेषीकृत आवासीय आवश्यकताओं वाले विशेषक्षेत्री घटक सर्वाधिक सुभेद्य घटकों में से हैं। इस संदर्भ में, हिमालय का जैवविविधता वाला तप्तस्थल, जो विशेषक्षेत्री विविधता से संपन्न है, जलवायु परिवर्तन के प्रति सुभेद्य है। इसके खतरों में, आनुवंशिक संसाधनों और जातियों, आवासों का सम्भावित क्षय और सहगामी रूप से, पारितंत्र के लाभों में कमी का आना शामिल है। इसलिए, इस क्षेत्र के लिए संरक्षण योजनाएँ बनाते समय, निरूपक पारितंत्रों/आवासों में विशेषक्षेत्री घटकों के संरक्षण का अत्यंत महत्त्व हो जाता है।

उपर्युक्त को हासिल करने की दिशा में, हमें समकालीन संरक्षण उपागमों की ओर ध्यान अंतरित करना होगा, जिसमें संरक्षित क्षेत्र-प्रणालियों के बीच दृश्यभूमि स्तर की अंतसंयोजकता का प्रतिमान शामिल है। यह संकल्पना, जाति-आवास पर ध्यान केंद्रित करने की जगह जैवभौगोलिक परास को विस्तारित करने पर समावेशी ध्यान-संकेंद्रण करने का पक्षसमर्थन करती है, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्राकृतिक समंजन सीमित हुए बिना आगे बढ़ सकें।

Separate explanation videos are available in English & Hindi

अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं

<p>26 Consider the following statements: According to the passage, the adverse impact of climate change on an ecosystem can be a</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. permanent disappearance of some of its flora and fauna. 2. permanent disappearance of ecosystem itself. <p>Which of the statements given above is/are correct?</p> <p>(a) 1 only (b) 2 only (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1 nor 2</p> <p>27 Which one of the following statements best implies the need to shift toward contemporary conservation approach?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Exploitation of natural resources causes a stress on the Himalayan ecosystem. (b) Climate change alters precipitation patterns, causes episodes of drought and biotic interference. (c) The rich biodiversity, including endemic diversity, makes the Himalayan region a biodiversity hotspot. (d) The Himalayan biogeographic region should be enabled to adapt to climate change smoothly. <p>28 What is the most important message conveyed by the passage?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Endemism is a characteristic feature of Himalayan region. (b) Conservation efforts should emphasize on biogeographic ranges rather than on some species or habitats. (c) Climate change has adverse impact on the Himalayan ecosystem. (d) Without Himalayan ecosystem, the life of the communities of uplands and downstreams will have no sustenance. <p>29 With reference to the passage, the following assumptions have been made:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. To maintain natural ecosystems, exploitation of natural resources should be completely avoided. 2. Not only anthropogenic but also natural reasons can adversely affect ecosystems. 3. Loss of endemic diversity leads to the extinction of ecosystems. <p>Which of the above assumptions is/are correct?</p> <p>(a) 1 and 2 (b) 2 only (c) 2 and 3 (d) 3 only</p>	<p>26 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए: परिच्छेद के अनुसार, पारितंत्र पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावस्वरूप</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. इसके वनस्पतिजात और प्राणिजात में से कुछ का स्थायी विलोपन हो सकता है 2. स्वयं पारितंत्र का स्थायी विलोपन हो सकता है <p>उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?</p> <p>(a) केवल 1 (b) केवल 2 (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1, न ही 2</p> <p>27 निम्नलिखित में से किस एक कथन का सबसे सटीक निहितार्थ यह है कि समकालीन संरक्षण उपागम की ओर ध्यान अंतरित करने की आवश्यकता है?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हिमालय के पारितंत्र पर दबाव डालता है (b) जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षण प्रतिरूपों में बदलाव, अनावृष्टि की घटनाएँ और जीवीय हस्तक्षेप होता है (c) समृद्ध जैवविविधता, जिसमें विशेषक्षेत्री विविधता शामिल है, हिमालय क्षेत्र को एक जैवविविधता तमस्थल बनाता है (d) हिमालय के जैवभौगोलिक क्षेत्र को इस तरह समर्थ बनाना चाहिए कि वह अबाध रूप से जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल बनता रहे <p>28 इस परिच्छेद द्वारा क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण संदेश दिया गया है?</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) विशेषक्षेत्रीयता हिमालयी क्षेत्र की लाक्षणिक विशेषता है (b) संरक्षण प्रयासों का बल कतिपय जातियों या आवासों के स्थान पर जैवभौगोलिक परासों पर होना चाहिए (c) जलवायु परिवर्तन का हिमालय के पारितंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव हुआ है (d) हिमालय के पारितंत्र के अभाव में, उच्चभूमियों और अनुप्रवाह क्षेत्रों के समुदायों के जीवन का कोई धारण-आधार नहीं होगा <p>29 परिच्छेद के संदर्भ में, निम्नलिखित पूर्वधारणाएँ बनाई गई हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राकृतिक पारितंत्र बनाए रखनेके लिए, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का पूरी तरह परिहार किया जाना चाहिए 2. पारितंत्र को, न केवल मानवोद्भविक, बल्कि प्राकृतिक कारण भी प्रतिकूलतः प्रभावित कर सकते हैं 3. विशेषक्षेत्री विविधता के क्षय से पारितंत्र का विलोपन होता है। <p>उपर्युक्त धारणाओं में से कौन से सही है/हैं ?</p> <p>(a) 1 और 2 (b) केवल 2 (c) 2 और 3 (d) केवल 3</p>
<p>Official Answer key: 26 - a 27 - d 28 - b 29 - b</p>	
<p>Practice these questions yourself after gap of 1 week. See official answer key from here 1 सप्ताह के अंतराल के बाद इन प्रश्नों का अभ्यास स्वयं करें। आधिकारिक उत्तर कुंजी देखें https://allinclusiveias.files.wordpress.com/2024/02/csar-official-answer-key-till-2022.pdf</p>	
<p>Separate explanation videos are available in English & Hindi अंग्रेजी और हिंदी में अलग-अलग वीडियो उपलब्ध हैं</p>	
<p>www.allinclusiveias.com</p>	<p>UPSC / PCS CSAT Class-06 Page-045 © All Inclusive IAS</p>